13 मई 2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. एक नेक इरादे वाला अध्ययन और एक जनसांख्यिकीय मिथक (13 मई) (GS PAPER I: समाज, मानव भूगोल)
2. भारत-ईएफटीए व्यापार समझौते से निवेश सबक (13 मई) (GS PAPER III: बाहरी क्षेत्र, GS PAPER II: भारत-यूरोप)
3. मामूली पलटाव: आईआईपी डेटा पर (13 मई) (GS PAPER III: उद्योग)
4. 'सप्तपदी' पर भ्रम दूर करना (13 मई) (GS PAPER I: सोसायटी)
5. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (GS PAPER II: सरकारी योजना)
6. डिजीलॉकर क्या है और क्या यह आपके डेटा और दस्तावेज़ों को सुरक्षित रखता है? (13 मई) (GS PAPER III: एस एंड टी)
7. हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) (GS PAPER III: निवेश)

PatriotICAS

एक सुविचारित अध्ययन और जनसांख्यिकीय मिथक (13 मई) (GS PAPER I: समाज, मानव भूगोल)

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बहस को पुनर्जीवित कर दिया है, लेकिन तथ्यों को सामने लाने की आवश्यकता है

- प्रधानमंत्री **की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएम-ईएसी) की रिपोर्ट** का निष्कर्ष है कि भारत में मुसलमानों सहित धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं और उन्हें किसी प्रकार का भेदभाव या उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता है।
- हालाँकि, रिपोर्ट की टाइमिंग, पुराने आंकड़ों का उपयोग, तथा कुछ जनसांख्यिकीय रुझानों को उजागर करने में विफलता ने विवाद को जन्म दिया है।
- इसमें बौद्ध आबादी के हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख किया गया है, लेकिन मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- कुछ लोगों का तर्क है कि यह रिपोर्ट हिंदुत्व के उस मिथक को बढ़ावा देती है कि हिंदुओं पर अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनने का खतरा मंडरा रहा है।
- भारत में तथाकथित मुस्लिम शासन के दौरान हिंदुओं के बहुसंख्यक होने का ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है।
- यह रिपोर्ट **बहुसंख्यक का दर्जा बनाए रखने के लिए हिंदुओं की जन्म दर बढ़ाने की वकालत करने वाले बयानों से जुड़ी है।**
- वर्तमान में **भारत की जनसंख्या में हिन्दू** 79.80% **हैं, जबकि मुस्लिम** 14.23% **हैं।**
- जनसांख्यिकीविदों का सुझाव है कि संख्यात्मक दृष्टि से अत्यधिक लाभ होने के कारण, हिंदुओं की बहुसंख्यक स्थिति को कोई वास्तविक खतरा नहीं है।

बयानबाजी, छिपी हुई और अन्यथा

- कुछ नेता **'जनसंख्या जिहाद' का हवाला देते हुए ध्रुवीकरण की रणनीति अपनाते हैं,** इससे यह संकेत मिलता है कि भारत एक इस्लामिक राज्य बन सकता है।
- इस बयानबाजी की जड़ें ऐतिहासिक हैं; एक शताब्दी से भी पहले, 'ए डाइंग रेस' नामक एक पुस्तक ने न्यूजीलैंड में स्वदेशी आबादी के समान हिंदू आबादी में गिरावट की आशंका जताई थी।
- पुस्तक **में स्वीकार किया गया कि हिंदू संख्या में कोई वास्तविक कमी नहीं हुई है, लेकिन सवाल उठाया गया है कि क्या केवल प्रजनन दर से ही किसी समूह की स्थिति निर्धारित की जानी चाहिए ।**
- उच्च प्रजनन दर को अक्सर **निरक्षरता और खराब आर्थिक स्थितियों से जोड़ा जाता है ।**
- किसी समूह की भलाई का आकलन करते समय शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के साथ-साथ सत्ता संरचना में प्रतिनिधित्व पर भी विचार करना चाहिए।
- केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारत की बढ़ती मुस्लिम आबादी को उनकी भलाई के सबूत के रूप में उद्धृत किया और उनकी तुलना पाकिस्तान के मुसलमानों से की।
- भारत **दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और** 2050 **तक यहां हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की आबादी सबसे अधिक होगी।**
- दक्षिण एशिया के मुस्लिम बहुल देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों की तुलना में भारतीय मुसलमानों को अधिक अधिकार प्राप्त हैं।
- वित्त मंत्री का बयान अन्यत्र के मुसलमानों की तुलना में भारतीय मुसलमानों की सापेक्षिक खुशहाली को रेखांकित करता है।

PatriotICIAS

जनसंख्या आंकड़ों पर एक नजर

- जनसंख्या वृद्धि किसी समूह की स्थिति को आंकने का एकमात्र मापदंड नहीं है; **उच्च प्रजनन दर शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का संकेत दे सकती है।**
- साक्षरता दर में वृद्धि के कारण मुस्लिम प्रजनन दर में तेजी से गिरावट आई है।
- **2001 से 2011 तक के जनगणना आंकड़ों से मुस्लिम और हिंदू दोनों की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दिखती है।**
- **मुस्लिम कुल प्रजनन दर (टीएफआर) प्रतिस्थापन दर के करीब है** , जो स्थिरीकरण का संकेत है।
- जनसांख्यिकीविदों का अनुमान है कि सदी के अंत तक मुस्लिम जनसंख्या 18.8% पर स्थिर हो जाएगी, जबकि हिंदू बहुसंख्यक का दर्जा बरकरार रखेंगे।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने कहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो रही है, तथा कई राज्यों में **प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से नीचे पहुंच गई है।**
- बिहार में प्रजनन दर सबसे अधिक है, जो मुस्लिम आबादी वाले कुछ दक्षिणी राज्यों से भी अधिक है।
- **असम में मुस्लिम जनसंख्या में चिंताजनक वृद्धि के दावे आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं हैं; असम की जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत के समान है** ।
- जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन सरकार ने उनका समर्थन नहीं किया।
- उत्तर प्रदेश और असम ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक प्रस्तावित किए, लेकिन जनसांख्यिकीविद् जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बलपूर्वक उपायों का विरोध कर रहे हैं।

जबरदस्ती का प्रयोग प्रतिकूल है

- अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में विवाह की आयु, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
- आईसीसीपीआर जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने वाले देश के रूप में भारत को जनसंख्या नियंत्रण के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति अनिवार्य या बलपूर्वक जनसंख्या नियंत्रण नीतियों पर रोक लगाती है।
- मोदी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए हलफनामे में स्वीकार किया कि परिवार नियोजन में जबरदस्ती करना प्रतिकूल परिणाम देने वाला है।
- जनसंख्या संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जाना चाहिए, विशेषकर मुस्लिम लड़कियों के लिए।
- मुस्लिम शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों को तुष्टिकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि वे समुदाय में उच्च प्रजनन दर को संबोधित करने में मदद कर सकते हैं।

PatriotICAS

भारत-ईएफटीए व्यापार समझौते से निवेश सबक (13 मई) (GS PAPER III: **बाहरी क्षेत्र**, GS PAPER II: **भारत-यूरोप**)

भारत को एक स्पष्ट मुक्त व्यापार समझौता नीति की आवश्यकता है, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश कानूनों से निपटने में

- ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भारत की एफटीए (मुक्त व्यापार संघ) वार्ता मौजूदा संसदीय चुनावों के कारण रुकी हुई है।
- हालाँकि, भारत ने मार्च में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता हासिल किया।
- ईएफटीए में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।
- इस समझौते को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (एफटीए) कहा जाता है।
- भारत और ईएफटीए देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- व्यापार समझौतों में भारत द्वारा पारंपरिक रूप से विरोध किए जाने वाले पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों को शामिल करने के लिए उल्लेखनीय है।
- अर्थशास्त्री विश्वजीत धर ने समझौते में इन मुद्दों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है जो अपने सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1960 में यूरोप में यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मिलकर एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए की गई थी।

सदस्य देशों

ईएफटीए के वर्तमान में चार सदस्य देश हैं:

- आइसलैंड
- लिकटेंस्टाइन
- नॉर्वे
- स्विट्ज़रलैंड

महत्वपूर्ण कार्यों

- **मुक्त व्यापार समझौते**: ईएफटीए ने यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर के 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया है। ये एफटीए ईएफटीए और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को खत्म या कम करते हैं।
- **आर्थिक सहयोग**: ईएफटीए वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है।
- **एकल बाजार भागीदारी**: हालांकि ईयू के सीमा शुल्क संघ के सदस्य नहीं हैं, सभी ईएफटीए सदस्य यूरोपीय एकल बाजार में भाग लेते हैं, जिससे उन्हें यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (ईईए) के भीतर वस्तुओं, सेवाओं, लोगों और पूंजी की मुक्त आवाजाही तक पहुंच मिलती है।

Patriot IAS

- **शेंगेन क्षेत्र**: सभी ईएफटीए सदस्य भी शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं, जो सदस्य राज्यों के बीच पासपोर्ट-मुक्त यात्रा की अनुमति देता है।

शासन

ईएफटीए का सर्वोच्च शासी निकाय ईएफटीए परिषद है, जो राजदूत स्तर पर वर्ष में आठ बार और मंत्री स्तर पर वर्ष में दो बार बैठक करती है। संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विटजरलैंड में स्थित है, तथा ब्रुसेल्स और लक्जमबर्ग में इसके कार्यालय हैं।

ईएफटीए बनाम ईयू

ईएफटीए और ईयू के बीच मुख्य अंतर उनके एकीकरण के स्तर में है। जहां ईएफटीए मुक्त व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं ईयू एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है जिसमें गहन एकीकरण है, जिसमें एक साझा मुद्रा (यूरो), एक सीमा शुल्क संघ और विभिन्न नीति क्षेत्रों पर निकट सहयोग शामिल है।

निवेश पर

- भारत-ईएफटीए एफटीए में एक विस्तृत निवेश अध्याय शामिल है, जबकि हाल में ऑस्ट्रेलिया, यूएई और मॉरीशस के साथ हुए एफटीए में ऐसा नहीं था।
- यह अध्याय निवेश सुविधा पर केंद्रित है, संरक्षण पर नहीं।
- इसमें एक अनूठा प्रावधान शामिल है, जिसके तहत ईएफटीए देशों का लक्ष्य एफटीए लागू होने के 10 वर्षों के भीतर भारत में एफडीआई को बढ़ाकर 50 बिलियन डॉलर करना है, तथा इसके बाद अगले पांच वर्षों में 50 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त निवेश करना है।
- निवेश अध्याय के अनुच्छेद 7.1(3)(बी) का उद्देश्य भारत में दस लाख नौकरियों के सृजन को सुगम बनाना भी है।
- ये प्रावधान आचरण के दायित्व स्थापित करते हैं, जिसका अर्थ है विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने की आवश्यकता के बजाय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ईमानदार प्रयास।
- भारतीय वार्ताकारों की निवेश अध्याय में ऐसे नवीन दायित्वों को शामिल करने के लिए सराहना की जाती है, जो एफटीए या निवेश संधियों में असामान्य हैं।
- इससे ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ भविष्य की वार्ता के लिए एक प्रारूप तैयार होता है।

व्यापार और निवेश

- आर्थिक सिद्धांत व्यापार और निवेश के बीच घनिष्ठ संबंध पर जोर देता है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां उत्पादन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में फैला हुआ है।
- परिणामस्वरूप, एफटीए में आमतौर पर व्यापार और निवेश दोनों को नियंत्रित करने वाले नियम शामिल होते हैं।
- 2000 के दशक की शुरुआत में जापान, कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देशों के साथ भारत के एफटीए ने इस पैटर्न का पालन किया, जिसमें व्यापार नियमों के साथ-साथ निवेश सुरक्षा पर अध्याय शामिल थे।
- हालाँकि, भारत ने FTA 2.0 के साथ अपना दृष्टिकोण बदल दिया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून को अंतर्राष्ट्रीय निवेश कानून से अलग कर दिया।

PatriotIAS

- ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस और यूएई जैसे देशों के साथ हाल के एफटीए पूरी तरह से व्यापार नियमों पर केंद्रित हैं और निवेश सुरक्षा के प्रावधानों को छोड़ देते हैं।
- ऐसा प्रतीत होता है कि भारत एक ही देश के साथ व्यापार और निवेश के लिए अलग-अलग समझौतों पर बातचीत करना पसंद करता है, जैसा कि संयुक्त अरब अमीरात के मामले में देखा गया है।
- इस प्रवृत्ति के बाद, भारत और यूएई ने 2022 में एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए और बाद में एक द्विपक्षीय निवेश संधि में प्रवेश किया।
- व्यापार और निवेश समझौतों को अलग-अलग इकाई मानते हुए यूके के साथ भी इसी तरह की बातचीत चल रही है।
- भारत-ईएफटीए एफटीए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यापार समझौते के भीतर एक निवेश अध्याय शामिल है, जो व्यापार और निवेश कानून को अलग करने की हालिया प्रवृत्ति से अलग है।
- हालाँकि, यह निर्धारित करना जल्दबाजी होगी कि क्या यह एफटीए के प्रति भारत के दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि भविष्य के समझौतों पर भारत-ईएफटीए एफटीए का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है।

(13 **मई** 2024) **मुख्य अभ्यास प्रश्न**

सवाल: भारत को उच्च आर्थिक विकास पथ की ओर प्रेरित करने में एक स्पष्ट और व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) नीति के महत्व पर चर्चा करें। (250 शब्द/15 अंक)

उत्तर दृष्टिकोण
स्पष्ट और व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की भारत की आवश्यकता के साथ उत्तर प्रस्तुत करें।
स्पष्ट और व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के विभिन्न फोकस क्षेत्रों पर चर्चा करें
सकारात्मक निहितार्थ के साथ समापन करें।

उत्तर:

भारत का आर्थिक विकास प्रक्षेपवक्र उसकी व्यापार नीतियों, विशेष रूप से मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवसरों का लाभ उठाने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित एफटीए नीति महत्वपूर्ण है। यह निबंध भारत को उच्च आर्थिक विकास पथ की ओर प्रेरित करने में एक स्पष्ट और व्यापक एफटीए नीति के महत्व पर प्रकाश डालता है।

- बाज़ार पहुंच बढ़ाना:
    - एफटीए भागीदार देशों को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे भारतीय उद्योगों के लिए निर्यात में वृद्धि की सुविधा मिलती है।
    - एक स्पष्ट एफटीए नीति व्यापार की शर्तों को रेखांकित करती है, व्यवसायों के लिए अनिश्चितताओं को कम करती है और निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देती है।
- विदेशी निवेश आकर्षित करना:

PatioticIAS

- एक व्यापक एफटीए नीति खुले बाजारों और आर्थिक उदारीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत देकर एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाती है।
- एफटीए में निवेश सुरक्षा और सुविधा के प्रावधान विदेशी निवेशकों में विश्वास पैदा करते हैं, जिससे पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में वृद्धि होती है।

- व्यापार साझेदारी में विविधता लाना:
  - विभिन्न देशों और क्षेत्रों के साथ एफटीए में शामिल होकर, भारत पारंपरिक व्यापारिक भागीदारों पर अपनी निर्भरता कम करता है और भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करता है।
  - एक स्पष्ट एफटीए नीति भारत को उभरते बाजारों और विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश करके अपने निर्यात स्थलों को रणनीतिक रूप से विविधता लाने में सक्षम बनाती है।
- प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना:
  - एफटीए घरेलू उद्योगों को वैश्विक बाजारों में उजागर करके, दक्षता में सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
  - टैरिफ में कटौती और नियामक सामंजस्य जैसे व्यापार उदारीकरण उपायों के माध्यम से, एफटीए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं।
- संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान:
  - एक व्यापक एफटीए नीति भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर कृषि संबंधी अक्षमताओं और विनिर्माण बाधाओं जैसी संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान कर सकती है।
  - वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के साथ-साथ सीमा पार निवेश को सुविधाजनक बनाकर, एफटीए क्षेत्रीय सुधारों और उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं।

इस प्रकार, एक स्पष्ट और व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नीति भारत को उच्च आर्थिक विकास पथ की ओर प्रेरित करने में सहायक है। बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, विदेशी निवेश को आकर्षित करके, व्यापार साझेदारी में विविधता लाकर, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देकर और संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करके, एफटीए आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। इसलिए, भारत के लिए एफटीए वार्ता के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना और टिकाऊ और समावेशी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को अधिकतम करने वाली नीतियों का निर्माण सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

मामूली पलटाव: आईआईपी डेटा पर (13 मई) (GS PAPER III: उद्योग)

औद्योगिक उत्पादन में मामूली वृद्धि कुछ चिंताजनक संकेत प्रस्तुत करती है

- अनुकूल आधार प्रभावों के बावजूद, **भारत की फ़ैक्टरी उत्पादन वृद्धि फरवरी में 5.6% से घटकर मार्च में 4.9% हो गई ।**
- खनन उत्पादन में 1.2% की वृद्धि हुई, जो 19 महीने का निचला स्तर है, जबकि विनिर्माण उत्पादन 5.2% तक बढ़ गया, जो पाँच महीने का उच्चतम स्तर है।
- मार्च 2023 में संकुचन के मुकाबले बिजली उत्पादन 8.6% बढ़ गया।

- **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय** ताजा सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान में 2023-24 के लिए औद्योगिक उत्पादन में 5.8% की वृद्धि को शामिल किया जाएगा।
- अधिकांश वार्षिक वृद्धि खनन (7.5%) से हुई, जबकि विनिर्माण में 5.5% की हल्की वृद्धि देखी गई।
- पूंजीगत वस्तुओं और बुनियादी ढांचे/निर्माण वस्तुओं ने लगातार दूसरे वर्ष मजबूत उत्पादन वृद्धि दर्ज की।
- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में क्रमशः 3.6% और 4% की वृद्धि हुई, जो सुस्त घरेलू खपत संकेतों को दर्शाता है।
- **निजी उपभोग वृद्धि** उत्पादन मामूली रहा है, उत्पादन अभी भी पूर्व-कोविड स्तर से नीचे है।
- **सामान्य से बेहतर मानसून की उम्मीद** इससे ग्रामीण मांग में वृद्धि हो सकती है, लेकिन सख्त ऋण शर्तें शहरी खपत को प्रभावित कर सकती हैं।
- महामारी के बाद से असमान उपभोग वसूली, उच्च आय वाले परिवारों की मांग से प्रेरित।
- **व्यापक मांग सुधार और निजी निवेश के लिए रोजगार सृजन और वास्तविक मजदूरी वृद्धि महत्वपूर्ण है।**
- **रोजगार-प्रधान विनिर्माण क्षेत्रों के बारे में** चिंताएं वर्ष 2023-24 में इसमें गिरावट आने की संभावना है, तथा कमजोर निर्यात भी मंदी में योगदान देगा।
- नवीनतम आईआईपी आंकड़ों से गति में कमी का पता चलता है, जिसमें जनवरी और मार्च के बीच विकास दर तीन तिमाहियों के निम्नतम स्तर 4.9% पर आ गई है।
- अगली सरकार को उपभोक्ता विश्वास से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने तथा निवेशकों को अपनी चिंताएं व्यक्त करने के लिए मंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

आईआईपी क्या है?
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) भारत में औद्योगिक उत्पादों की एक श्रृंखला के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन का एक माप है। यह अनिवार्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के विकास को ट्रैक करता है, जिनमें शामिल हैं:

- खुदाई
- बिजली
- उत्पादन

आईआईपी को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, जो कि एमओएसपीआई (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय) के तहत एक विभाग है, संदर्भ माह समाप्त होने के छह सप्ताह बाद।

आईआईपी क्यों महत्वपूर्ण है?
आईआईपी भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह आर्थिक रुझानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, नीतियां बनाने में मदद करता है और विभिन्न उद्योगों के प्रदर्शन की निगरानी करता है। आईआईपी का विश्लेषण करके, अर्थशास्त्री और नीति निर्माता अनुमान लगा सकते हैं:

- औद्योगिक विकास दर
- विशिष्ट क्षेत्रों का प्रदर्शन
- उत्पादन स्तर में उतार-चढ़ाव
- सरकारी नीतियों का प्रभाव

आधार वर्ष और कवरेज

PatriotIAS

आईआईपी का एक आधार वर्ष होता है, जो एक संदर्भ बिंदु होता है जिसके आधार पर उत्पादन में होने वाले बदलावों को मापा जाता है। आईआईपी के लिए वर्तमान आधार वर्ष 2011-2012 है, जिसका अर्थ है कि उस वर्ष उत्पादन स्तर को 100 का सूचकांक दिया गया है। आईआईपी में औद्योगिक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिन्हें निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- व्यापक क्षेत्र: खनन, विनिर्माण और बिजली
- उपयोग-आधारित क्षेत्र: मूल वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं

आठ प्रमुख उद्योग

जबकि आईआईपी एक व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करता है, आठ मुख्य उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये आठ मुख्य उद्योग, आईआईपी में उनके भार के साथ, इस प्रकार हैं:

1. रिफाइनरी उत्पाद (17.92%)
2. बिजली (15.22%)
3. स्टील (11.64%)
4. कोयला (4.35%)
5. कच्चा तेल (4.12%)
6. प्राकृतिक गैस (2.68%)
7. सीमेंट (2.44%)
8. उर्वरक (1.89%)

क्लिकबेट पेपर: ईएसी-पीएम वर्किंग पेपर पर (13 मई)

जनसांख्यिकीय बदलावों को सीधे राज्य की कार्रवाइयों से जोड़ना समस्याग्रस्त है

- अर्थशास्त्री शमिका रवि और सह-लेखकों के हालिया वर्किंग पेपर ने भारत में धार्मिक जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चर्चा करके विवाद पैदा कर दिया है।
- यह पेपर अमेरिका से संबद्ध शोधकर्ताओं द्वारा संकलित राज्यों के धार्मिक विशेषताओं डेटासेट, 2017 पर आधारित है।
- **यह भारत की जनसंख्या में हिंदुओं के अनुपात में 84.68% से 78% (1950-2015) की गिरावट पर प्रकाश डालता है, साथ ही मुस्लिम आबादी में 9.84% से 14% की वृद्धि हुई है।**
- लेखकों का कहना है कि बहुसंख्यक धर्म के अनुयायियों में यह गिरावट एक वैश्विक प्रवृत्ति है, यह केवल भारत के लिए नहीं है।
- वे इन जनसांख्यिकीय बदलावों के लिए विशिष्ट कारण नहीं बताते हैं, लेकिन सुझाव देते हैं कि भारत में बढ़ती मुस्लिम संख्या मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा के दावों का खंडन करती है।
- लेखक भारत की स्थिति की तुलना पाकिस्तान और बांग्लादेश से करते हैं, जहां "जनसांख्यिकीय झटके" के कारण हिंदू अल्पसंख्यकों का अनुपात कम हो गया।
- हालाँकि, वे भारत में मुस्लिम संख्या में वृद्धि का श्रेय "प्रगतिशील नीतियों और समावेशी संस्थानों" को देते हैं।

PatriotICIAS

- आलोचकों का तर्क है कि इस शोधपत्र में सम्पूर्ण विश्लेषण और स्पष्टीकरण का अभाव है, यह अधूरे आंकड़ों पर आधारित है तथा अप्रमाणित निष्कर्ष निकालता है।
- आर्थिक **सलाहकार परिषद द्वारा इस पेपर का समर्थन करने से इसकी विश्वसनीयता और उद्देश्य पर चिंता उत्पन्न होती है।**

'सप्तपदी' पर भ्रम दूर करना (13 मई) (GS PAPER I: समाज)

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में वही बात दोहराई गई है जो हिंदू विवाह अधिनियम की एक धारा को पढ़ने से हमें पता चलती है।

- **डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल मामले में सुप्रीम कोर्ट के** हालिया फैसले को लेकर गलतफहमी है ।
- कुछ लोगों का मानना है कि इस निर्णय का तात्पर्य यह है कि यदि सप्तपदी समारोह नहीं किया जाता है तो हिंदू विवाह वैध नहीं है।
- हालाँकि, न्यायालय ने न तो स्पष्ट रूप से यह कहा, न ही उसने अन्य समारोहों पर चर्चा की जो विवाह को वैध ठहरा सकते थे।
- निर्णय में उन प्रचलित प्रथाओं पर भी विचार नहीं किया गया जहां मालाओं का आदान-प्रदान जैसे साधारण समारोह ही पर्याप्त होते हैं।
- **हिंदू विवाह अधिनियम,** 1955 **में** संशोधन पर भी विचार नहीं किया। तमिलनाडु में धारा 7(ए) के माध्यम से विवाह का "सुया मरियाधई" रूप शुरू किया गया।

अदालत के समक्ष मामला

- यह मामला पत्नी द्वारा अपने पति की तलाक याचिका को बिहार के मुजफ्फरपुर से झारखंड के रांची स्थानांतरित करने के लिए दायर स्थानांतरण याचिका से संबंधित है।
- दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से संविधान की धारा 142 के तहत अपने विवाह को अवैध घोषित करने के लिए आवेदन किया।
- उन्होंने दावा किया कि उनकी शादी 7 मार्च, 2021 को होने वाली थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण वादिक जनकल्याण समिति (पंजीकृत) से 7 जुलाई, 2021 को विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया।
- उन्होंने **उत्तर प्रदेश पंजीकरण नियम,** 2017 **के तहत पंजीकरण की मांग की और 'विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र' प्राप्त किया।**
- हिंदू विवाह समारोह की योजना के बावजूद, उनके बीच मतभेद पैदा हो गए, जिसके कारण पति ने तलाक के लिए अर्जी दायर की।
- **पक्षों ने स्वीकार किया कि उनके बीच कोई हिंदू विवाह नहीं हुआ था, इसलिए विवाह प्रमाणपत्र का कोई महत्व नहीं था।**

PatriotiCAS

- उन्होंने अदालत से यह घोषित करने का अनुरोध किया कि कोई शादी नहीं हुई है और उन्हें शादी की समाप्ति के डिक्री के सामान्य कानूनी उपाय का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति दी जाए।
- हिंदू **विवाह अधिनियम के अनुसार हिंदू विवाह को केवल पारंपरिक संस्कारों और समारोहों के अनुसार संपन्न किया जाना आवश्यक है।**
- **सप्तपदी, सात चरणों वाला अनुष्ठान, सभी हिंदू संप्रदायों में सार्वभौमिक रूप से प्रचलित नहीं है** ।
- अधिनियम में कहा गया है कि यदि सप्तपदी को शामिल किया जाता है, तो विवाह सातवें चरण के साथ पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सप्तपदी विवाह समारोह का एकमात्र रूप नहीं है, यह दोहराते हुए कि विवाह समारोहों को लागू रीति-रिवाजों या उपयोग का पालन करना चाहिए।

पिछले निर्णय

- यह मामला हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के संबंध में मौजूदा कानून को दोहराता है।
- अकेले पंजीकरण से विवाह संपन्न नहीं हो सकता; इसे एक समारोह का पालन करना चाहिए।
- **तमिलनाडु ने 1967 में विवाह समारोहों को सरल बनाने के लिए एक संशोधन पारित किया, जिसमें बिना पुजारी के विवाह की अनुमति दी गई।**
- **एस. नागलिंगम बनाम शिवगामी** (2001) **में, मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक वैध विवाह बिना पुजारी के हो सकता है यदि पक्ष खुद को जीवनसाथी घोषित करते हैं और माला पहनाने या अंगूठियों का आदान-प्रदान करने जैसा समारोह करते हैं।**
- **इलावरसन बनाम पुलिस अधीक्षक और अन्य** (2023) इस फैसले को बरकरार रखा और बालाकृष्णन बनाम पुलिस इंस्पेक्टर (2014) मामले में पिछले फैसले से असहमति जताई, जिसमें गुप्त विवाह को अमान्य माना गया था।
- न्यायालय ने तर्क दिया कि सार्वजनिक अनुष्ठान की आवश्यकता जोड़ों को खतरे में डाल सकती है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है।
- **इलावरासन में, विवाह एक वकील के कक्ष में हुआ, जिसे न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इसे वैवाहिक स्थापना नहीं माना जा सकता है।**
- हालाँकि, यदि वकील अपनी व्यक्तिगत क्षमता में गवाह के रूप में कार्य करते हैं, तो उनकी भूमिका वैध थी।

तृणमूल बनाम तृणमूल (13 मई)

पुराने नेताओं और नए नेतृत्व के बीच मतभेद पार्टी को प्रभावित कर रहा है

- तृणमूल कांग्रेस को मौजूदा लोकसभा चुनावों में भाजपा और वाम-कांग्रेस गठबंधन से चुनावी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- तृणमूल के भीतर पुराने नेताओं और नए नेतृत्व के बीच आंतरिक विभाजन स्पष्ट है।

Parmar IAS

- पार्टी में नए चेहरों की मांग बढ़ रही है, लेकिन टिकट आवंटन में नेतृत्व रूढ़िवादी बना हुआ है।
- सौगत रॉय और सुदीप बनर्जी जैसे वरिष्ठ सदस्यों को मैदान में उतारा गया, जिससे आलोचना हुई।
- कुणाल घोष ने सुदीप बनर्जी पर विभिन्न कमियों का आरोप लगाया, जिससे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी उठानी पड़ी।
- भाजपा उम्मीदवार तापस रॉय टिकट न मिलने पर तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए।
- कुणाल घोष की टिप्पणी से तृणमूल को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जिसके कारण उन्हें प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया।
- ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी युवा उम्मीदवारों को नामांकित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- अभिषेक बनर्जी के उदय के बावजूद, ममता बनर्जी निर्णय लेने में प्रेरक शक्ति बनी हुई हैं।
- इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या अनुभवी पुराने नेताओं या ऊर्जावान युवा खिलाड़ियों को चुना जाना चाहिए।
- भाजपा और वाम-कांग्रेस गठबंधन से मिल रही चुनावी चुनौतियों के बीच तृणमूल नेतृत्व ने एकता बनाए रखने का आग्रह किया।

बच्चों की संख्या का संबंध धर्म से अधिक विकास से है (13 मई)

लड़कियों को शिक्षित करने, बाल विवाह रोकने और परिवार नियोजन उपायों तक पहुंच बढ़ाने से प्रजनन स्तर में कमी आएगी

- हालिया चर्चाओं ने एक बार फिर भारत में मुस्लिम आबादी की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करने का जिक्र किया.
- अप्रैल 2023 के आंकड़ों से पता चला कि 2019-21 में मुसलमानों की प्रजनन दर 2.36 थी, जो 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर के करीब थी।
- प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कहा कि 1950 से 2015 तक जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 43.15% बढ़ी, जबकि हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घट गई।
- सामाजिक-आर्थिक कारक, धर्म नहीं, मुख्य रूप से लोगों द्वारा चुने जाने वाले बच्चों की संख्या को प्रभावित करते हैं।
- लड़कियों को शिक्षित करना, विवाह में देरी करना, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परिवार नियोजन उपायों तक पहुंच सुनिश्चित करना प्रजनन स्तर को कम करता है।
- मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होती है, जैसे बिहार में 3.6, महाराष्ट्र में 2.0, तमिलनाडु में 1.9, कर्नाटक में 2.0, झारखंड में 2.7 और राजस्थान में 2.4।
- मुस्लिम महिलाओं के बीच प्रजनन स्तर में क्षेत्रीय अंतर को राज्य के आर्थिक और सामाजिक रूप से विकास के स्तर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

PatriotIAS

Chart 1: Percentage share of women aged 20-24 years who got married before becoming an adult (horizontal axis) against the Muslim fertility rate, as of 2019-21

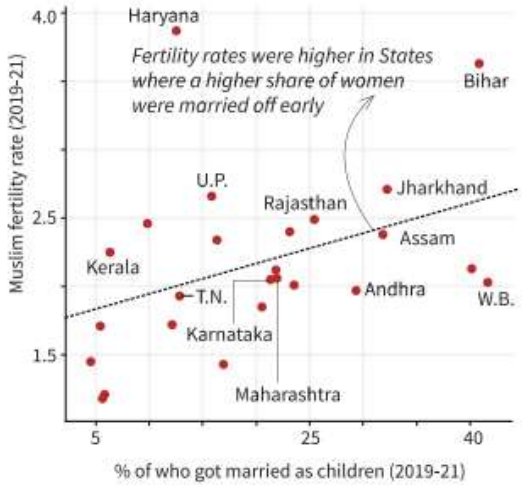

Chart 2: Percentage share of the female population who were literate (horizontal axis) against the Muslim fertility rate, as of 2019-21

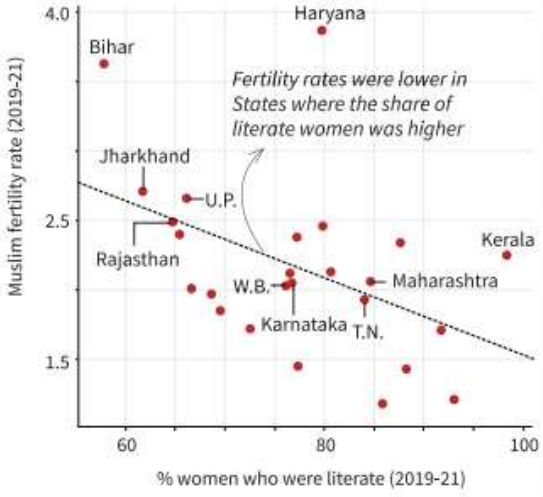

Chart 3: The chart shows the share of men and women who said that they never heard or saw a message about family planning via radio/ TV/newspapers/wall paintings or the internet in 2019-21, across select religions

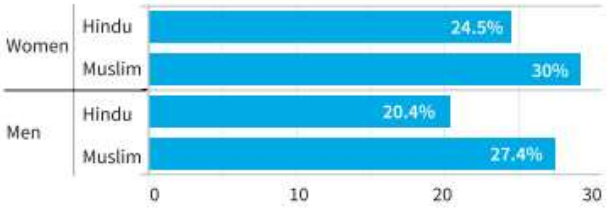

Chart 4: The share of unmet demand for family planning among Hindu ● and Muslim ✖ women across select States in 2019-21. Unmet demand refers to the share of women who want to limit or space out children, but are unable to do so

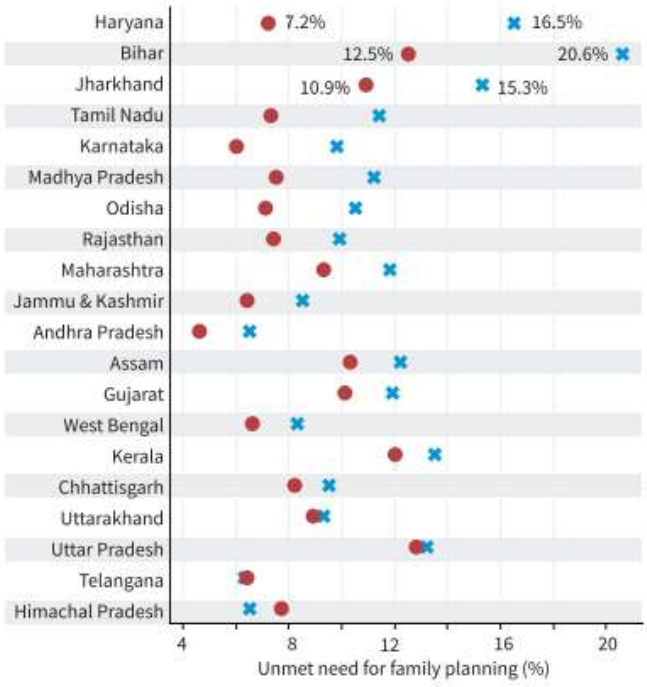

- चार्ट 1 2019-21 में 20-24 आयु वर्ग की महिलाओं की कम उम्र में शादी करने वाली महिलाओं के प्रतिशत और मुस्लिम प्रजनन दर के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध दिखाता है, जो कम उम्र में शादी करने वाले राज्यों में उच्च प्रजनन दर का संकेत देता है।
- चार्ट 2 साक्षर महिलाओं के प्रतिशत और मुस्लिम प्रजनन दर के बीच एक नकारात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, जो महिलाओं के बीच उच्च साक्षरता दर वाले राज्यों में कम प्रजनन दर का सुझाव देता है।
- परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता की कमी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, 25% हिंदू महिलाओं और 30% मुस्लिम महिलाओं ने बताया कि उन्होंने विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से परिवार नियोजन के बारे में संदेश कभी नहीं सुना या देखा है (चार्ट 3)।
- जागरूकता के बावजूद, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कई महिलाओं को परिवार नियोजन उपायों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे मांग पूरी नहीं हो पाती है। चार्ट 4 से पता

चलता है कि अधिकांश राज्यों में, हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाओं में परिवार नियोजन की अपूर्ण मांग अधिक है।

- मुस्लिम महिलाओं के बीच उच्च प्रजनन दर वाले राज्य, जैसे कि हरियाणा, बिहार और झारखंड, मुस्लिम और हिंदू महिलाओं के बीच व्यापक अंतर के साथ, उच्च अपूर्ण मांग भी प्रदर्शित करते हैं।
- गर्भनिरोधक उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में सुधार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना धार्मिक समूहों में प्रजनन दर को कम करने के लिए आवश्यक सरकारी कार्य हैं।

प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका लक्ष्य 2024 तक "सभी के लिए आवास" हासिल करना है। यह दो उप-योजनाओं के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को पूरा करती है: प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ग्रामीण आवास और शहरी आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY-G), पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, यह 2016 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के (स्थायी) घर प्रदान करना है।

महत्वपूर्ण जानकारी:

- लॉन्च: 1 अप्रैल 2016
- मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय
- लक्ष्य: ग्रामीण परिवार गरीबी रेखा से नीचे
- लाभ: पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता

लक्ष्य:

पीएमएवाई-जी का प्राथमिक लक्ष्य 2024 तक "सभी के लिए आवास" हासिल करना है। यह पहल ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पक्के घर प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करती है।

पात्रता:

पीएमएवाई-जी के लिए पात्रता मानदंड सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और राज्य के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। यहां एक सामान्य दिशानिर्देश है:

- आवेदक को ग्रामीण परिवार से संबंधित होना चाहिए।

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 25 जून 2015 को भारत सरकार द्वारा सभी पात्र शहरी परिवारों को 2 **स्लम पुनर्विकास और क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी द्वारा किफायती "पक्के" (स्थायी) घर प्रदान करने के लिए** शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। . मिशन को शुरू में 2022 तक पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है।

PMAY-U के लिए कौन पात्र है?

पीएमएवाई-यू योजना का लक्ष्य निम्नलिखित है:

लाभार्थी:

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): इस श्रेणी को घर खरीदने के लिए योजना के तहत पूरी सहायता मिलती है।
- निम्न आय समूह (एलआईजी): एलआईजी लाभार्थी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र हैं।
- मध्यम आय समूह (एमआईजी I और II): एलआईजी के समान, एमआईजी श्रेणियां सीएलएसएस के माध्यम से लाभ उठा सकती हैं।

पीएमएवाई-यू की मुख्य विशेषताएं:

- कार्यान्वयन के लिए चार कार्यक्षेत्र:

- सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले के रूप में पहचाना जाना चाहिए।
- पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- महिला सदस्यों वाले परिवारों, विकलांग लोगों, एससी/एसटी समुदायों और बेघर परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।

फ़ायदे:

PMAY-G पात्र लाभार्थियों को पक्का घर बनाने के लिए किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान राशि घर के प्रकार और भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्न होती है।

- लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी)
- साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)
- इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर)
- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस)

- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस): यह घटक एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को गृह ऋण पर ब्याज दर में छूट प्रदान करता है।
- किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी): एक उप-योजना पीएमएवाई-यू के तहत शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थलों के निकट किफायती किराये के आवास तक आसान पहुंच प्रदान की गई है।

वर्तमान स्थिति (अगस्त 2022 तक):

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएमएवाई-यू को 31 दिसंबर, 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। हालांकि, यह विस्तार केवल पहले से स्वीकृत घरों (सीएलएसएस को छोड़कर) के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लागू होता है।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) भारतीय शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे और शासन में सुधार के लिए 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बड़े पैमाने की पहल थी।

यहां भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के आधिकारिक स्रोतों के आधार पर जेएनएनयूआरएम मिशन का सारांश दिया गया है:

- **लॉन्च**: 3 दिसंबर 2005
- **लक्ष्य**: पहचाने गए शहरों में सुधारों को प्रोत्साहित करना और तेजी से योजनाबद्ध विकास करना
- **फोकस क्षेत्र**: शहरी बुनियादी ढांचे और सेवा वितरण में दक्षता, सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय निकायों की जवाबदेही
- **निवेश**: सात वर्षों में $20 बिलियन से अधिक
- **अवयव**:

PatriotIAS

- उप-मिशन 1: शहरी बुनियादी ढाँचा और प्रशासन (यूआईडीजी)
- उप-मिशन 2: शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएँ (बीएसयूपी)

जेएनएनयूआरएम के उद्देश्य

जेएनएनयूआरएम का लक्ष्य "आर्थिक रूप से उत्पादक, कुशल, न्यायसंगत और उत्तरदायी शहर" बनाना है:

- शहरों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन
- शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करना
- सुधारों के माध्यम से नगरपालिका प्रशासन को मजबूत करना

जेएनएनयूआरएम की उपलब्धियां

जेएनएनयूआरएम मिशन को पूरे भारत में शहरी बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार का श्रेय दिया जाता है। इसकी कुछ उपलब्धियों में शामिल हैं:

- कई शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में सुधार हुआ
- मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रमों में निवेश
- शहरी नियोजन और विकास पर अधिक ध्यान

वर्तमान स्थिति

जेएनएनयूआरएम मिशन को 2015 में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) द्वारा सफल बनाया गया था [6]। हालांकि जेएनएनयूआरएम अब एक सक्रिय मिशन नहीं है, इसकी विरासत भारत में शहरी विकास नीतियों को आकार देती रहती है।

मुझे MoHUA की आधिकारिक वेबसाइट पर जेएनएनयूआरएम से सीधे संबंधित कोई भी चित्र नहीं मिला। हालाँकि, आप वेब पर खोज कर विभिन्न शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (सड़कों, पुलों, जल उपचार संयंत्रों) को दर्शाने वाली छवियां पा सकते हैं जो संभवतः जेएनएनयूआरएम मिशन के तहत शुरू की गई थीं।

PatriotIAS

स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने इस्तीफा क्यों दिया? (13 मई)

ब्यूट हाउस सत्ता साझेदारी समझौता क्या था? समझौता क्यों टूट गया?

- स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) के नेता जॉन स्वाइनी ने स्कॉटलैंड के पहले मंत्री के रूप में शपथ ली है।
- यह नियुक्ति अप्रैल में प्रथम मंत्री पद **और एसएनपी के नेतृत्व से हमजा यूसुफ के इस्तीफे के बाद हुई है।**
- **जलवायु लक्ष्यों को छोड़ने के स्कॉटिश ग्रीन्स के फैसले के कारण एसएनपी के बिजली-साझाकरण समझौते को स्कॉटिश ग्रीन्स के साथ समाप्त करने के बाद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया।**

एसएनपी की परेशानियां क्या हैं?

- स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) को अपने वित्त से संबंधित शिकायतों के कारण 2021 से उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है।
- जुलाई 2021 में पुलिस ने इन शिकायतों की जांच के लिए ऑपरेशन ब्रांचफॉर्म लॉन्च किया.
- पूर्व प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने फरवरी 2023 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
- एसएनपी के वित्त की पुलिस जांच के सिलसिले में स्टर्जन को जून 2023 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया था।
- स्टर्जन के पति और एसएनपी के पूर्व मुख्य कार्यकारी पीटर म्यूरेल को अप्रैल 2024 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर पार्टी फंड के गबन का आरोप लगाया गया था।

सत्ता साझेदारी समझौता क्या था?

- ब्यूट हाउस स्कॉटिश प्रथम मंत्री का आधिकारिक निवास है।
- ब्यूट हाउस पावर शेयरिंग समझौता, जिसे सहयोग समझौते के रूप में भी जाना जाता है, अगस्त 2021 में स्कॉटिश सरकार और स्कॉटिश ग्रीन पार्टी संसदीय समूह के बीच हस्ताक्षरित किया गया था।
- इस समझौते का उद्देश्य स्कॉटिश संसद के सत्र के दौरान स्कॉटलैंड के लिए प्रभावी और जिम्मेदार नेतृत्व प्रदान करना था।
- समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू जलवायु संकट का समाधान करना था।

श्री यूसुफ के इस्तीफे के कारण क्या हुआ?

- 18 अप्रैल को, स्कॉटलैंड के नेट ज़ीरो मंत्री, मायरी मैकएलन ने संसद में घोषणा की कि सरकार ने अंतरिम 2030 लक्ष्य अप्राप्य होने के कारण अपने तत्काल जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को छोड़ दिया है।
- सुश्री मैकएलन के अनुसार, सरकार का लक्ष्य 2045 के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करना है जो व्यवहार्य, निष्पक्ष और न्यायसंगत हो।
- जलवायु परिवर्तन समिति (सीसीसी) की 2023 की रिपोर्ट में महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में स्कॉटलैंड की विफलता पर प्रकाश डाला गया है, जो 2021 में अपने वार्षिक उत्सर्जन लक्ष्य से चूक गया है, जो 12 वर्षों में आठवीं ऐसी चूक है।
- सीसीसी द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने, 2045 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए कानूनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने और वार्षिक प्रगति रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए कानून में तेजी लाई जाएगी।
- 2030 के लक्ष्य को ख़त्म करने के बावजूद, स्कॉटलैंड 2045 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- उसी दिन, स्कॉटलैंड की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने अपने विशेषज्ञ लिंग क्लिनिक द्वारा रेफर किये गए बच्चों को यौवन अवरोधक दवाएं देने पर रोक लगा दी।
- स्कॉटिश ग्रीन्स की LGBTQ शाखा ने इस निर्णय के बाद SNP के साथ पार्टी के समझौते के भविष्य के बारे में चिंता व्यक्त की।

PatriotiCIAS

- एसएनपी ने 2030 के जलवायु लक्ष्य को रद्द करने के बाद 25 अप्रैल को स्कॉटिश ग्रीन्स के साथ ब्यूट हाउस सत्ता-साझाकरण समझौते को समाप्त कर दिया।
- स्कॉटिश ग्रीन्स ने एसएनपी की आलोचना करते हुए इस निर्णय को राजनीतिक कायरतापूर्ण कार्य बताया।
- समझौते की समाप्ति के बाद, एसएनपी अल्पमत सरकार बन गयी जिसे स्कॉटिश संसद के अन्य सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी।
- एसएनपी सरकार 1 मई को अविश्वास प्रस्ताव से बच गई, और श्री स्विनी को प्रथम मंत्री बने रहने के लिए स्कॉटिश संसद में आवश्यक बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ।

स्कॉटिश ग्रीन्स के लिए आगे क्या है?

- श्री स्विनी को नामित करने के लिए मतदान के बाद, ग्रीन्स नेता सुश्री स्लेटर ने संसद को संबोधित किया।
- उन्होंने कहा कि एसएनपी प्रथम मंत्री के लिए ग्रीन पार्टी का समर्थन हमेशा सशर्त रहा है।
- यह शर्त जलवायु संकट से निपटने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों पर आधारित है।
- सुश्री स्लेटर ने सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान स्कॉटिश ग्रीन्स की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया।
- पार्टी अपनी उपलब्धियों और नीतियों के अनुसार, अधिक न्यायपूर्ण, हरित और अधिक समान स्कॉटलैंड के लिए वकालत करना जारी रखेगी।

डिजिलॉकर क्या है और क्या यह आपके डेटा और दस्तावेजों को सुरक्षित रखता है? (13 मई) (GS PAPER III: एस एंड टी)

2015 में लॉन्च किया गया डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक ऐप के रूप में काम करता है। मई की शुरुआत तक, ऐप में 270 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं, जबकि इसके माध्यम से लगभग 6.7 बिलियन दस्तावेज़ पुनर्प्राप्त किए गए हैं

- देश भर के छात्र अब भारत सरकार के **डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बोर्ड परीक्षा परिणाम और सत्यापित मार्कशीट तक पहुंच सकते हैं।**
- यह सुविधा सीआईएससीई बोर्ड के 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ-साथ तमिलनाडु राज्य बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए उपलब्ध है।
- जल्द ही यह सेवा सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए भी लागू होगी।
- **2015 में लॉन्च किया गया डिजीलॉकर, डिजिटल रिकॉर्ड संग्रहीत करने के लिए एक ऐप के रूप में कार्य करता है।**

PrimoIAS

- उपयोगकर्ता ऐप का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं जैसे **पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, मार्कशीट की समीक्षा करना या यात्रा के दौरान पहचान साबित करना।**
- **डिजिटल वॉलेट में आवश्यक दस्तावेजों तक आसान पहुंच, सत्यापन और भंडारण की अनुमति देकर कागज के उपयोग को कम करने की** भारत सरकार की पहल के अनुरूप है ।
- मई के आरंभ तक, इस ऐप के 270 **मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता थे और इसने आधार, बीमा पॉलिसियों, पैन रिकॉर्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित लगभग** 6.7 **बिलियन दस्तावेजों को पुनः प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है।**
- **डिजिलॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेजों को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधाएं प्रदान करने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम,** 2016 **के नियम** 9**ए के अनुसार मूल भौतिक दस्तावेजों के समकक्ष माना जाता है।**

उपयोगकर्ता डिजिलॉकर को क्यों अपना रहे हैं?

- डिजिलॉकर एक डिजिटल समाधान है जिसे उपयोगकर्ताओं को **उनके अद्यतन दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अपनी पहचान और प्रमाणिकता साबित करने की सुविधा मिलती है।**
- इससे सत्यापन अधिकारियों को **नकली, खराब गुणवत्ता वाली मुद्रित प्रतियों या महत्वपूर्ण विवरणों से रहित पुराने दस्तावेजों के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है।**
- डिजिलॉकर **यात्रा के दौरान भौतिक दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, क्योंकि वे उन्हें स्थानीय डिवाइस पर एक्सेस या संग्रहीत कर सकते हैं।**
- सिद्धांततः, डिजिलॉकर पर संग्रहीत डिजिटल दस्तावेजों को उनके मूल दस्तावेजों के समान ही वैध माना जाता है।
- डिजिलॉकर ऐप के उपयोग से संभावित रूप से **सेवा वितरण में तेजी आ सकती है**, जैसा कि डिजिलॉकर वेबसाइट पर बताया गया है।

डिजिलॉकर कितना सुरक्षित है?

- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)** की एक प्रमुख पहल है , जो सार्वजनिक क्लाउड पर एक सुरक्षित दस्तावेज़ एक्सेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है।
- यह एक सरकार द्वारा अनुमोदित एप्लिकेशन है जिसे सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ बनाए रखा गया है।
- **सुरक्षा उपायों में** 2048 **बिट आरएसए एसएसएल एन्क्रिप्शन, मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण (ओटीपी सत्यापन), सहमति प्रणाली, समयबद्ध लॉगआउट और सुरक्षा ऑडिट शामिल हैं।**
- हालाँकि, किसी भी सरकारी डेटाबेस की तरह, डिजिलॉकर उपयोगकर्ता डेटा चुराने की चाहत रखने वाले हैकर्स के लिए एक संभावित लक्ष्य है।
- जून 2020 में, डिजिलॉकर ने साइन-अप प्रक्रिया में एक संभावित भेद्यता को संबोधित किया जो खातों से समझौता कर सकती थी।

ParIIAS

- उपयोगकर्ता डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए CERT-In और स्वतंत्र शोधकर्ताओं से अलर्ट प्राप्त करने के बाद भेद्यता को तुरंत ठीक कर लिया गया।
- डिजिलॉकर द्वारा एकत्रित डेटा में फ़ाइलें और दस्तावेज (वैकल्पिक), नाम, ईमेल (वैकल्पिक) और उपयोगकर्ता आईडी शामिल हैं, साथ ही तीसरे पक्ष के साथ डेटा साझा नहीं करने और एन्क्रिप्टेड ट्रांजिट का आश्वासन भी शामिल है।

डिजिलॉकर से जुड़ी कुछ समस्याएं क्या हैं?

- **स्मार्टफोन या ऐप नेविगेशन से अपरिचित लोगों को डिजिलॉकर डाउनलोड करने, ओटीपी का उपयोग करने और सहायता के बिना अपने क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।**
- जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकते, उन्हें ऐप का उपयोग करने में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- एकाधिक नाम, उपनाम या असंगत वर्तनी वाले उपयोगकर्ताओं को अपने दस्तावेज़ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि डिजिलॉकर को जारीकर्ता डेटा के साथ सटीक मिलान की आवश्यकता होती है।
- यहां तक कि कैपिटलाइजेशन या आद्याक्षर जैसी छोटी सी विसंगतियां भी दस्तावेज़ पुनर्प्राप्ति में विफलता का कारण बन सकती हैं।
- **डिजीलॉकर के माध्यम से आभासी दस्तावेज़ स्वीकार करने में सरकारी अधिकारियों और कानून प्रवर्तन के बीच एकरूपता का अभाव** चुनौतियों को बढ़ाता है।
- डिजीलॉकर पर वर्चुअल दस्तावेज़ उपलब्ध होने के बावजूद कुछ लोग मूल हार्ड कॉपी पर जोर देते हैं।

क्या मुझे नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए डिजीलॉकर की आवश्यकता है?

- पासपोर्ट प्रसंस्करण के लिए डिजिलॉकर की आवश्यकता के बारे में पूछताछ करने के लिए द हिंदू ने पासपोर्ट सेवा से संपर्क किया।
- **नेशनल कॉल सेंटर के एक अधिकारी ने कहा कि केवल दस्तावेजों की मूल हार्ड कॉपी और ज़ेरॉक्स कॉपी की आवश्यकता थी, और डिजीलॉकर अनिवार्य नहीं था।**
- हालाँकि, अधिकारियों ने पहले पासपोर्ट आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डिजीलॉकर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है।
- ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों ने कागज की मूल प्रतियों का निरीक्षण करने के अलावा डिजीलॉकर के माध्यम से दस्तावेजों का अनुरोध किया।
- इस नीति का कार्यान्वयन देश भर में व्यापक रूप से भिन्न है।
- प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यक्ति मूल दस्तावेज, भौतिक प्रतियां और आवश्यक प्रमाण-पत्र डिजिलॉकर पर रख कर तैयारी कर सकते हैं।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) (GS PAPER III: निवेश)

PatriotICIAS

यह यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल है जिसका उपयोग भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण, निर्माण और संचालन के लिए किया जाता है, खासकर सड़क क्षेत्र में। इसमें दो अन्य पीपीपी मॉडल की विशेषताएं शामिल हैं: बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (टोल) (बीओटी) एन्युटी और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी)।

हैम की मुख्य विशेषताएं

- **परियोजना लागत का बंटवारा**: सरकार अग्रिम निर्माण लागत का एक हिस्सा (आमतौर पर 40%) वहन करती है, जिसे निर्माण के दौरान हासिल किए गए लक्ष्यों से जुड़ी किश्तों में वितरित किया जाता है। निजी डेवलपर शेष 60% का वित्त पोषण करता है - उनकी इक्विटी और ऋण का संयोजन।
- **वार्षिकी भुगतान**: **परियोजना पूरी होने के बाद, सरकार** शेष परियोजना लागत और संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) खर्चों की भरपाई के लिए डेवलपर को रियायती अवधि (आमतौर पर 30 वर्ष) के लिए अर्ध-वार्षिक निश्चित वार्षिकी भुगतान करती है।
- **टोल संग्रह**: सरकार राजमार्ग पर टोल संग्रह के लिए जिम्मेदार है और इसे डेवलपर के साथ साझा नहीं करती है।
- **डेवलपर का चयन**: डेवलपर्स का चयन उनकी उद्धृत परियोजना लागत के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) और रियायती अवधि के दौरान ओ एंड एम खर्चों के आधार पर पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

HAM **के लाभ**

- **सरकारी वित्तीय बोझ कम**: अग्रिम लागत को साझा करके, HAM केवल परियोजना के वित्तपोषण की तुलना में सरकार पर तत्काल वित्तीय बोझ को कम करता है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि**: यह मॉडल वार्षिकी के माध्यम से सुनिश्चित रिटर्न और अपने निवेश को पुनर्प्राप्त करने के अवसर के संयोजन की पेशकश करके निजी डेवलपर्स को आकर्षित करता है।
- **परियोजना का तेजी से पूरा होना**: समय पर मील के पत्थर आधारित भुगतान डेवलपर्स को निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
- **जोखिम का हस्तांतरण**: यातायात में उतार-चढ़ाव और टोल संग्रहण दक्षता का जोखिम सरकार वहन करती है।

यहां कुछ संबंधित चित्र दिए गए हैं जिन्हें आप वेब सर्च पर पा सकते हैं लेकिन मैं उन्हें सीधे प्रदर्शित नहीं कर सकता:

- भारत में निर्माणाधीन राजमार्ग का चित्र।
- एचएएम में सरकार और डेवलपर के बीच परियोजना लागत के बंटवारे को दर्शाने वाला ग्राफ।
- HAM मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करने वाला एक चार्ट।

PatriotIAS

सुअर की किडनी प्रत्यारोपित करवाने वाले पहले व्यक्ति रिचर्ड "रिक" स्लेमैन का निधन इस अभूतपूर्व प्रक्रिया के लगभग दो महीने बाद हो गया। यहाँ मुख्य विवरणों का सारांश दिया गया है:

- **प्राप्तकर्ता**: रिचर्ड "रिक" स्लेमैन
- **आयु**: 62
- **स्थिति**: अंतिम चरण की किडनी की बीमारी
- **अस्पताल**: मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल, बोस्टन
- **प्रत्यारोपण की तिथि**: मार्च 2024
- **मृत्यु का कारण**: अपुष्ट, मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल ने कहा कि उनके निष्कर्षों से यह संकेत नहीं मिलता कि प्रत्यारोपण इसमें योगदान देने वाला कारक है।

कामी रीता शेरपा (जन्म 17 जनवरी 1970) एक नेपाली शेरपा पर्वतारोहण गाइड हैं।

- **"एवरेस्ट मैन" के नाम से प्रसिद्ध कामी रीता ने** रिकॉर्ड तोड़ 29 बार चोटी पर चढ़ाई की है, जिससे उन्होंने मई 2023 में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
- नेपाल के सोलुखुम्बु जिले के थामे में जन्मे कामी रीता पर्वतारोहियों के परिवार से आते हैं। उनके पिता एक गाइड थे और उनके भाई लकपा रीता 17 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं।
- कामी रीता ने 1992 में एक कुली के रूप में अपनी एवरेस्ट यात्रा शुरू की, उसके बाद वे गाइड बन गए।
- उन्होंने 1994 में 24 वर्ष की आयु में अपना पहला शिखर हासिल किया था और तब से लगभग हर वर्ष एवरेस्ट पर चढ़ते रहे हैं।

कामी रीता के समर्पण और कौशल ने उन्हें पर्वतारोहण की दुनिया में एक किंवदंती बना दिया है। वे महत्वाकांक्षी पर्वतारोहियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं और शेरपा लोगों की शारीरिक शक्ति के प्रमाण हैं।

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध (लैंडलॉक) है और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) का सदस्य है? ए) आइसलैंड बी) नॉर्वे सी) लिकटेंस्टीन डी) स्विटजरलैंड	**उत्तर**: C) लिकटेंस्टीन **व्याख्या**: लिकटेंस्टीन एक स्थलरुद्ध देश है और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) का सदस्य है। आइसलैंड स्थलरुद्ध नहीं है, और नॉर्वे और स्विटजरलैंड दोनों EFTA के सदस्य नहीं हैं।
प्रश्न 2: ईएफटीए सदस्यों में से कौन सा देश यूरोप में स्थित नहीं है? ए) आइसलैंड बी) लिकटेंस्टीन सी) नॉर्वे डी) स्विटजरलैंड	**उत्तर**: A) आइसलैंड **व्याख्या**: आइसलैंड यूरोप में स्थित है, जबकि लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड भी यूरोपीय देश हैं।
प्रश्न 3 : यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए) ईएफटीए की स्थापना 1957 में हुई थी। बी) ईएफटीए में पांच सदस्य देश शामिल हैं। सी) ईएफटीए का लक्ष्य यूरोपीय संघ (ईयू) के समान एकल बाजार बनाना है। डी) ईएफटीए सदस्यता केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित है।	**उत्तर**: **बी)** ईएफटीए में पांच सदस्य देश शामिल हैं। **स्पष्टीकरण**: ईएफटीए में वर्तमान में चार सदस्य देश शामिल हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। इसलिए, विकल्प बी सही है। विकल्प ए गलत है क्योंकि ईएफटीए की स्थापना 1960 में हुई थी। विकल्प सी गलत है क्योंकि ईएफटीए का लक्ष्य अपने सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है लेकिन ईयू की तरह एकल बाजार बनाना नहीं चाहता है। विकल्प डी गलत है क्योंकि ईएफटीए सदस्यता केवल यूरोपीय देशों तक ही सीमित नहीं है; उदाहरण के लिए, मध्य यूरोप में भूमि से घिरा देश होने के बावजूद लिकटेंस्टीन इसका सदस्य है।
प्रश्न 4: नकारात्मकता पूर्वाग्रह क्या है? क) नकारात्मक घटनाओं की अपेक्षा सकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की प्रवृत्ति। बी) नकारात्मक उत्तेजनाओं से बचने की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति।	**उत्तर**: C) सकारात्मक उत्तेजनाओं की अपेक्षा नकारात्मक उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि। **स्पष्टीकरण**: नकारात्मकता पूर्वाग्रह मनुष्यों में निहित एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, जहां व्यक्ति सकारात्मक उत्तेजनाओं की

PatriotICAS

सी) सकारात्मक उत्तेजनाओं की अपेक्षा नकारात्मक उत्तेजनाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता। D) एक संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह जो व्यक्तियों को अत्यधिक आशावादी बनाता है।	तुलना में नकारात्मक उत्तेजनाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए, विकल्प C सही है। विकल्प ए गलत है क्योंकि नकारात्मकता पूर्वाग्रह में नकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शामिल है, न कि सकारात्मक घटनाओं पर। विकल्प बी गलत है क्योंकि नकारात्मकता पूर्वाग्रह में नकारात्मक उत्तेजनाओं से बचना शामिल नहीं है बल्कि उनके प्रति अधिक संवेदनशील होना शामिल है। विकल्प डी गलत है क्योंकि नकारात्मकता पूर्वाग्रह नकारात्मक परिणामों पर अधिक जोर देता है, जिससे व्यक्ति अत्यधिक आशावादी होने के बजाय अधिक सतर्क या निराशावादी बन जाता है।
प्रश्न 4: नकारात्मकता पूर्वाग्रह सामाजिक अंतःक्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है? ए) विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देकर। बी) जोखिम लेने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित करके। सी) व्यक्तियों में लचीलापन को बढ़ावा देकर। D) व्यक्तियों को रिश्ते बनाने में अधिक सतर्क बनाकर।	**उत्तर**: D) व्यक्तियों को रिश्ते बनाने में अधिक सतर्क बनाकर। **व्याख्या**: नकारात्मकता पूर्वाग्रह व्यक्तियों को संबंध बनाने में अधिक सतर्क बनाता है क्योंकि वे संभावित खतरों या नकारात्मक अनुभवों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए, विकल्प D सही है। विकल्प A, B और C गलत हैं क्योंकि नकारात्मकता पूर्वाग्रह सामाजिक संबंधों के संदर्भ में व्यक्तियों में विश्वास और सहयोग को बढ़ावा नहीं देता है, जोखिम लेने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करता है या लचीलापन नहीं बढ़ाता है।
प्रश्न 5 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) क्या मापता है? ए) औद्योगिक क्षेत्र में मुद्रास्फीति दर बी) औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर सी) विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का स्तर डी) व्यक्तिगत उद्योगों की उत्पादकता	**उत्तर**: **बी)** औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर **स्पष्टीकरण** : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक विशिष्ट अवधि में विभिन्न उद्योगों के उत्पादन स्तर में परिवर्तन का विश्लेषण करके औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर को मापता है। इसलिए, विकल्प बी सही है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि आईआईपी मुद्रास्फीति, रोजगार स्तर या व्यक्तिगत उद्योगों की उत्पादकता को नहीं मापता है।
प्रश्न 6: निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र IIP द्वारा कवर नहीं किया गया है? ए) खनन बी) विनिर्माण सी) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) डी) बिजली	**उत्तर**: **सी)** न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) **व्याख्या**: IIP मुख्य रूप से खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों को कवर करता है, लेकिन इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) शामिल नहीं है। इसलिए, विकल्प C सही है। विकल्प A, B और D

PatriotIAS

	गलत हैं क्योंकि वे उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो IIP द्वारा कवर किए जाते हैं।
प्रश्न 7 : औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) क्या मापता है? ए) कृषि उत्पादकता बी) विनिर्माण उत्पादन सी) सेवा क्षेत्र की वृद्धि डी) खुदरा बिक्री प्रदर्शन	**उत्तर**: **बी**) विनिर्माण उत्पादन **स्पष्टीकरण**: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन को मापता है, जिससे विकल्प बी सही हो जाता है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि आईआईपी विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि कृषि उत्पादकता, सेवा क्षेत्र की वृद्धि या खुदरा बिक्री प्रदर्शन पर।
प्रश्न 8: कथन: IIP की गणना औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा और मूल्य के आधार पर की जाती है। कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए) आईआईपी की गणना केवल उत्पादित वस्तुओं के मूल्य के आधार पर की जाती है। बी) आईआईपी की गणना केवल उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के आधार पर की जाती है। सी) आईआईपी की गणना उत्पादित वस्तुओं की मात्रा और मूल्य, साथ ही उनकी गुणवत्ता के आधार पर की जाती है। डी) आईआईपी की गणना उपभोग की गई वस्तुओं की मात्रा और मूल्य के आधार पर की जाती है।	**उत्तर**: **बी**) आईआईपी की गणना केवल उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के आधार पर की जाती है। **स्पष्टीकरण**: दिया गया कथन गलत है। IIP की गणना औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा के आधार पर की जाती है, न कि उनके मूल्य के आधार पर। इसलिए, विकल्प B सही है। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि वे IIP की गणना में विचार किए गए कारकों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।
प्रश्न 9 : कथन: जेएनएनयूआरएम (जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन) ने शहरी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A) जेएनएनयूआरएम केवल दस लाख से कम आबादी वाले शहरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। B) जेएनएनयूआरएम ने केवल ग्रामीण क्षेत्रों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।	**उत्तर**: C) जेएनएनयूआरएम ने शहरी विकास परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की। **स्पष्टीकरण**: दिया गया कथन सही है। JNNURM ने वास्तव में शहरी विकास परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की। इसलिए, विकल्प C सही है। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि वे JNNURM के लाभार्थियों और उद्देश्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं ।

PatriotIAS

C) जेएनएनयूआरएम ने शहरी विकास परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की। D) जेएनएनयूआरएम ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की ।	
प्रश्न 10: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? क) ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार बी) कृषि विकास को बढ़ावा देना सी) शहरी बुनियादी ढांचे और शासन को बढ़ाना डी) उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना	**उत्तर**: C) शहरी बुनियादी ढांचे और शासन को बढ़ाना **व्याख्या**: JNNURM का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे और शासन को बढ़ाना था। इसका उद्देश्य शहरी विकास परियोजनाओं के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। विकल्प A और B गलत हैं क्योंकि JNNURM ने ग्रामीण विकास पर नहीं बल्कि शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित किया। विकल्प D गलत है क्योंकि JNNURM ने उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की।
प्रश्न 11: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसे वित्तीय सहायता प्राप्त हुई? ए) राज्य सरकारें बी) ग्रामीण विकास एजेंसियां सी) निजी कंपनियाँ डी) कृषि सहकारी समितियाँ	**उत्तर**: **ए)** राज्य सरकारें **स्पष्टीकरण**: जेएनएनयूआरएम ने शहरी विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान की। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि वे जेएनएनयूआरएम की वित्तीय सहायता के लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
प्रश्न 12: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की अवधि क्या थी? ए) 5 वर्ष बी) 10 वर्ष सी) 15 वर्ष डी) 20 वर्ष	**उत्तर**: **ए)** 5 वर्ष स्पष्टीकरण : जेएनएनयूआरएम को शुरुआत में 5 साल की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था । इसे दो चरणों में लागू किया गया था, चरण I 2005 से 2012 तक और चरण II 2013 से 2014 तक। विकल्प बी, सी और डी गलत हैं क्योंकि वे लंबी अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जेएनएनयूआरएम की वास्तविक अवधि के साथ संरेखित नहीं होते हैं।
प्रश्न 13: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ए) ग्रामीण विकास मंत्रालय बी) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय सी) वित्त मंत्रालय	**उत्तर**: **बी)** आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय **स्पष्टीकरण**: आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भारत में प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि वे सीधे

PatriotIAS

डी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	पीएमएवाई (शहरी) के कार्यान्वयन से संबंधित नहीं हैं।
प्रश्न 14: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, निम्नलिखित में से कौन घरों के निर्माण या वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र है? ए) राज्य सरकारें बी) शहरी स्थानीय निकाय सी) ग्रामीण विकास एजेंसियां डी) निजी कंपनियाँ	**उत्तर**: **बी**) शहरी स्थानीय निकाय **व्याख्या**: शहरी स्थानीय निकाय घरों के निर्माण या सुधार के लिए PMAY (शहरी) के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि वे PMAY (शहरी) वित्तीय सहायता के लाभार्थियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
प्रश्न 15 : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत, निम्नलिखित में से कौन घरों के निर्माण या विस्तार के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र है? ए) राज्य सरकारें बी) शहरी स्थानीय निकाय सी) ग्रामीण विकास एजेंसियां डी) लाभार्थी परिवार	**उत्तरः** D) लाभार्थी परिवार **स्पष्टीकरण** : लाभार्थी परिवार घरों के निर्माण या वृद्धि के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि वे पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत इच्छित लाभार्थियों के अलावा अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रश्न 16: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, निम्नलिखित में से कौन घरों के निर्माण या वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र है? ए) राज्य सरकारें बी) शहरी स्थानीय निकाय सी) ग्रामीण विकास एजेंसियां डी) लाभार्थी परिवार	**उत्तर**: **डी**) लाभार्थी परिवार **स्पष्टीकरण**: लाभार्थी परिवार घरों के निर्माण या वृद्धि के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि वे पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत इच्छित लाभार्थियों के अलावा अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रश्न 17: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, निम्नलिखित में से कौन घरों के निर्माण या वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र है? ए) राज्य सरकारें बी) शहरी स्थानीय निकाय सी) ग्रामीण विकास एजेंसियां डी) लाभार्थी परिवार	**उत्तर**: **डी**) लाभार्थी परिवार **स्पष्टीकरण**: लाभार्थी परिवार घरों के निर्माण या वृद्धि के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं। विकल्प ए, बी और सी गलत हैं क्योंकि वे पीएमएवाई (शहरी) के तहत इच्छित लाभार्थियों के अलावा अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
प्रश्न 18: डिजीलॉकर के प्रबंधन के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? ए) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बी) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सी) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय D) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	**उत्तर**: **बी**) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **व्याख्या**: डिजिलॉकर का प्रबंधन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा किया जाता है। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि वे डिजिलॉकर के प्रबंधन से असंबंधित मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

PatriotICAS

प्रश्न 19: डिजिलॉकर कागजी कार्रवाई को कम करने में कैसे योगदान देता है? अ) भौतिक दस्तावेजों के उपयोग को बढ़ाकर। बी) उपयोगकर्ताओं को डिजिटल दस्तावेजों का प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता होती है। C) डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहीत करने और उन तक पहुंचने के लिए एक मंच प्रदान करके। घ) कागज आधारित दस्तावेज़ीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित करके।	**उत्तर**: C) डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहीत करने और उन तक पहुँचने के लिए एक मंच प्रदान करके। **स्पष्टीकरण**: डिजिलॉकर उपयोगकर्ताओं को उनके दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियों को संग्रहीत करने और उन तक पहुँचने के लिए एक सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करके कागजी कार्रवाई को कम करता है, जिससे भौतिक कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम हो जाती है। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि वे सटीक रूप से वर्णन नहीं करते हैं कि डिजिलॉकर कागजी कार्रवाई को कम करने में कैसे योगदान देता है।
प्रश्न 20: हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? A) एचएएम बैंकों द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार की निवेश योजना है। बी) एचएएम एक मॉडल है जिसका उपयोग कृषि वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने के लिए किया जाता है। C) एचएएम एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल है जिसका उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाता है। D) HAM एक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तकनीक है।	**उत्तर**: C) एचएएम एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल है जिसका उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किया जाता है। **स्पष्टीकरण**: हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) एक प्रकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल है जिसका उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से सड़कों और राजमार्ग क्षेत्र में किया जाता है। विकल्प ए, बी और डी गलत हैं क्योंकि वे एचएएम की प्रकृति या उद्देश्य का सटीक वर्णन नहीं करते हैं।
प्रश्न 21 : हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) के तहत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र क्या भूमिका निभाता है? ए) निजी क्षेत्र केवल तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। बी) निजी क्षेत्र परियोजना वित्तपोषण और निर्माण के लिए जिम्मेदार है। C) HAM परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की कोई भागीदारी नहीं है। D) निजी क्षेत्र एक नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।	**उत्तर**: **बी**) निजी क्षेत्र परियोजना वित्तपोषण और निर्माण के लिए जिम्मेदार है। **व्याख्या**: हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) के तहत परियोजनाओं में, निजी क्षेत्र परियोजना के वित्तपोषण और निर्माण के लिए जिम्मेदार है, जबकि सरकार निश्चित वार्षिक भुगतान प्रदान करने और परियोजना की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। विकल्प A, C और D गलत हैं क्योंकि वे HAM परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भूमिका का सटीक वर्णन नहीं करते हैं ।
प्रश्न 22: हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) के तहत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को निश्चित वार्षिक भुगतान प्रदान करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? ए) निजी क्षेत्र का संघ	**उत्तरः सी**) सरकार **स्पष्टीकरण**: हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) के तहत परियोजनाओं में, सरकार निजी क्षेत्र को निश्चित वार्षिक भुगतान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ये भुगतान निर्माण और रखरखाव

PatriotIAS

बी) अंतर्राष्ट्रीय संगठन सी) सरकार डी) नियामक प्राधिकरण	दोनों लागतों को कवर करते हैं और निजी क्षेत्र को राजस्व निश्चितता प्रदान करते हैं। विकल्प A, B और D गलत हैं क्योंकि वे HAM परियोजनाओं में भुगतान करने के लिए जिम्मेदार इकाई का सटीक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

PatrioticIAS